(ख) इन परियोजनाओं की वित्तीय बंदी संबंधित तेल कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं के बीच निर्भर करता है।

(ग) और (घ) सरकार ने बीना, मध्य प्रदेश में 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता की एक रिफाइनरी की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 5277 करोड़ रुपये है।

(ङ) और (च) इस परियोजना के अक्तूबर, 2002 तक पूरी हो जाने की आशा है। इस परियोजना का इक्विटी ढांचा निम्नानुसार प्रस्तावित है:—

— भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और ओमान आयल कं० लि०, प्रत्येक 26 प्रतिशत (549 करोड़ रुपये)

— तृतीय पक्षकारों सहित जनसाधारण, 48 प्रतिशत (1013 करोड़ रुपये)

— ऋण (3166 करोड़ रुपये)

'दानिक्स' तथा 'दास' अधिकारियों द्वारा हड़ताल

*145. **श्री रामजीलाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, अण्डमान और निकोबार आइलैण्ड सिविल सर्विसेज (दानिक्स) तथा दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवाएं (दास) के अधिकारी कब से कब तक हड़ताल पर रहे;

(ख) उनकी मांगें क्या थीं तथा इन मांगों पर केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण क्या है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने उक्त अधिकारियों की मांगें माने जाने हेतु अपनी अनुशंसा भेजी है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय कर लेगी तथा निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि बड़ी संख्या में दानिक्स और कुछ दास अधिकारी 24.9.1998 से 9.10.1998 तक की अवधि के दौरान कभी-कभी ड्यूटी पर नहीं आए।

(ख) दानिक्स अधिकारी सेवा के एन्ट्री ग्रेड 2000-3500 रु० (संशोधन पूर्व) को 2200-4000 रु० (संशोधन पूर्व) में बढ़ाए जाने और 4500-5700 रुपए (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में उच्चतम पद पर नया ग्रेड शुरू करने के बारे में पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने इस सेवा के वेतन और ग्रेड संरचना के बारे में पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की अनुशंसा की है।

(घ) मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और इस बारे में अन्तिम निर्णय शीघ्र लिए जाने की संभावना है।

Private Investment for Development of Tourism in North-East

*148. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the North-Eastern region can be converted into a tourist paradise, if properly planned and developed;

(b) whether Government have any time-bound scheme for creation of tourist spots in the region;

(c) if so, the location of spots identified and the amount earmarked thereon; and

(d) the details of programmes and procedure finalised to attract private investment for developing tourist resorts in the North-Eastern region and achievement made, so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI OMAK APANG): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Identification and development of Tourist Spots is primarily the responsibility of the State Governments. However, Ministry of Tourism extends Central Financial Assistance for creation of Tourist Infrastructure to the State Governments on receipt of specific project proposals their inter se priority and availability of funds.

The Ministry of Tourism constituted a Task Force to study the special problems of the North East Region and draw up specific schemes and projects for the development of tourism. The Task Force in its Report has identified major tourist centres in the region for tourism development in consultation with the State Governments. The Report has recommended upgradation of Guwahati Airport with